क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा द्वारा फरीदाबाद की मज़दूर बस्तियों का सर्वे

विलासिता के साये में गटर, अध्यात्म और बीमारी का कृष्णा नगर

सत्यवीर सिंह

2011 की जनगणना के अनुसार, दिल्ली की दक्षिण की सीमा से सटे, हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले की कुल आबादी 18,09,733 और फरीदाबाद महानगर की आबादी 14,14,050 थी. कोरोना का बहाना बनाकर, जातिगत गणना की असुविधाजनक मांग से बचने के लिए, मोदी सरकार ने 2021 में जनगणना कराई ही नहीं। 2020 के आधार कार्ड आधारित आंकड़ों के अनुसार 2022 में फरीदाबाद ज़िले की अनुमानित आबादी 19,44,196 तथा फरीदाबाद महानगर की अनुमानित आबादी 16.5 लाख है। मज़दूरों की कुल आबादी 10 लाख से अधिक है। फरीदाबाद में कुल 60 मज़दूर बस्तियां हैं।

नीलम चौक से बाटा चौक के बीच, रेलवे लाइन के पूरब में बसी कॉलोनी, कृष्णा नगर मज़दूर बस्ती, सेक्टर 56 ए, फरीदाबाद-121004, के नाम से जानी जाती है। मेट्रो के बाटा चौक के गेट न 3 से उतरेंगे, तो सामने अमीरों की आलीशान शानो-शौकत और वीभत्स विलासिता का शाहकार पांच सितारा होटल 'रेडिसन ब्लू' नज़र आता है। इस होटल की दक्षिणी कंपाउंड वाल के बाहर से रेलवे लाइन की ओर जाने वाला रास्ता कृष्णानगर जाने का मुख्य रास्ता है। जैसे ही होटल पीछे छूटेगा, सामने असली हिंदुस्तान नज़र आएगा। सबसे पहले गटर के बदबूदार पानी की एक विशाल झील दिखाई पड़ेगी, जिसमें सूअर अठखेलियाँ कर रहे होते हैं। 'स्वच्छ भारत अभियान' का ये दृश्य होटल रेडिसन ब्लू के 'गेस्ट्स' को नज़र ना आए, इसलिए होटल के कमरों की पश्चिम वाली खिड़कियों पर गहरे रंग के अपारदर्शी शीशे दूर-नीचे से ही नज़र पड़ जाते हैं।

कोई हैरानी नहीं होती, जब बस्ती में सबसे पहले, एक आध्यात्मिक आश्रम नज़र आता है, "देवेन्द्र कृष्ण सेवाधाम"। इस आश्रम का दूसरा नाम दिलचस्प है 'भारतीय नागरिक महासंघ'। इस आश्रम के मालिक से जब उनका शुभ नाम पूछा गया, तो उन्होंने तफ्शील से बताया; "मेरा नाम डी. के. झा (देवेन्द्र कृष्ण झा) है, मैथिलि ब्राह्मण हूँ, सीता मैया के गाँव सीतामढ़ी, बिहार का रहने वाला हूँ और मैं 1986 में यहाँ आया था। तब ही से लोगों की आध्यात्मिक सेवा कर रहा हूँ।" वे दूसरे गेरुवा वस्त्रधारी 'साधुओं' से कुछ बातों में अलग भी नज़र आए-- वहाँ चिलम नहीं चल रही थी, कई मज़दूर जो वहाँ बैठे बतिया रहे थे, उनमें एक मुस्लिम भी थे, और सभी बिलकुल सहज बैठे छाँव का आनंद ले रहे थे। पूरब से गटर वाली झील की बदबू, नाक को जला रही थी लेकिन वहाँ उपस्थित लोग सहज थे। एक और खास बात, झा साहब 6 सितम्बर को जंतर-मंतर पर मज़दूरों के विस्थापन की विकराल होती जा रही समस्या पर हुए प्रदर्शन में कई लोगों को लेकर पहुंचे थे और वहाँ मंच पर विराजमान थे। मतलब सामाजिक सरोकार तो है।

हर मज़दूर बस्ती में अध्यात्म की पाठशाला ज़रूर होती है। इसका एक दिलचस्प पहलू ये भी है, कि अध्यात्म की राजनीति में पूर्णकालिक कार्यकर्ता (whole timers), क्रांतिकारी राजनीति की अपेक्षा कहीं अधिक हैं। झा साहब 1986 में बिहार राज्य के सीतामढ़ी शहर से अध्यात्म के पूर्णकालिक कार्यकर्ता की तरह ही घर से निकल पड़े थे। उन्होंने किसी योजना के अंतर्गत या नोकरी के आश्वासन पर घर नहीं छोड़ा था। फरीदाबाद पहुंचकर कृष्णा नगर झुग्गी बस्ती में डेरा डाल दिया और अध्यात्म की प्रैक्टिस करने लगे। लोग जुटते गए और कारवां बनता गया। ये काम क्रांतिकारी राजनीति करने वाला कोई व्यक्ति भी कर सकता था। वह भी यहाँ आकर, क्रांतिकारी वर्ग चेतना लाने के लिए मज़दूरों को संगठित करता तो मज़दूर उसे भी भूखों नहीं मरने देते। आध्यात्मवादियों की हम कितनी भी आलोचना करें, लेकिन यदि हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता, क्रांतिकारी राजनीति की प्रैक्टिस करने नहीं निकलेंगे और आध्यात्म की प्रैक्टिस करने वाले पूर्णकालिक कार्यकर्ता निकलते जाएँगे, तो लोग क्रांतिकारी राजनीति नहीं बल्कि आध्यात्मिक राजनीति ही सीखेंगे। इसके लिए लोगों को कसूरवार ठहराना उचित नहीं।

1980 के शुरू से ही ये मज़दूर बस्ती बसती गई। मथुरा रोड पर रोड किनारे व्यवसायिक क्षेत्र के पश्चिम और रेलवे लाइन के पूरब में, चूँकि जगह बहुत सीमित है, इसलिए ये बस्ती छोटी है। कुल आबादी 10,000 के क़रीब है। बस्ती में नए बने 5 शौचालय नज़र आते हैं, लेकिन वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। शौचालय में पानी की व्यवस्था ना हो तो वह ना होने से भी ख़तरनाक हो जाता है। इन शौचालयों में इतनी बदबू और गन्दगी है कि उनके नज़दीक जाना भी संभव नहीं। ये बीमारियों के स्रोत बने खड़े हैं। प्रशासनिक अधिकारीयों और मंत्रियों-संत्रियों के शौचालयों के पानी की आपूर्ति कुछ बंद कर दी जाए, शायद तब उन्हें ये बात मालूम पड़ेगी कि शौचालयों में पानी आपूर्ति होना कितना आवश्यक है। अधिकतर लोग रेलवे पटरियों के किनारे ही शौच को जाने को मज़बूर हैं। कभी भी यहाँ आज़ाद नगर की गुड़िया जैसा हादसा हो सकता है। बाक़ी

सभी मामलों में कृष्णा नगर बस्ती, दूसरी मज़दूर बस्तियों जैसे ही है; अपार गन्दगी, टूटी गलियां, सीवर का बहता पानी, बीमार-पीले नज़र आते मज़दूर। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। एक जगह पूछा, 'आपको सस्ते सरकारी गल्ले की दुकान से राशन मिलता है?' जवाब आया, 'कैसा सरकारी राशन साब?' एक स्कूल वहाँ ज़रूर है। स्कूल यूनीफोर्म में, जिसकी जेब पर डॉ अम्बेडकर की तस्वीर लगी है, घूमते बच्चों को देखकर बहुत अच्छा लगा। एक बच्चे को जब 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चे' की पम्फलेट दी, तो वह मुस्कुराता हुआ उसे जोर-जोर से पढ़ने लगा। सारी थकावट दूर हो गई।

सारी बस्ती में कहीं बैठकर चाय पीने का स्थान नज़र नहीं आया लेकिन वहाँ RWA का दफ्तर बहुत ही आधुनिक सुसज्जित, ए सी लगा हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी की बड़ी-बड़ी तस्वीरों से सज़ा हुआ है। युवा सचिव महोदय, भाजपा के पूर्व मंत्री विपुल गोएल, जो भाजपा के अंदरूनी सत्ता संघर्ष में हांसीए से भी बाहर फेंक दिए गए हैं, के क़सीदे पढ़ते नज़र आए। काश, आज वो होते!!! बस्ती तो वैसी ही होती, शायद सचिव महोदय के पास कार और लम्बी होती!!

सभी मज़दूरों को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण राशन और जो उसे भी खरीदने लायक नहीं बचे, उन्हें मुफ़्त राशन देने की व्यवस्था की जाए। सभी मज़दूर बस्तियों में सरकार को तत्काल पर्याप्त आकार के सुलभ शौचालयों का निर्माण युद्ध स्तर पर शुरू करना चाहिए, जिसके रख-रखाव के खर्च की ज़िम्मेदारी नगर निगम कि हो। यहाँ स्वच्छता अभियान की नितांत आवश्यकता है। साफ-सफाई की व्यवस्था तत्काल की जाए। एक बात नोट की जाए कि मज़दूर बस्तियों में पैदा हुए कीटाणु-विषाणु सरकारी अनुमति से नहीं उड़ते!! कृष्णा नगर के सड़े शौचालय से पैदा कीटाणु सेक्टर 15 में स्थित डीसी और जजों की कोठियों, मंत्रियों के बंगलों तक पहुँचने के लिए किसी की इज़ाज़त नहीं लेंगे.

मालिक और मज़दूर के बीच बैर की वज़ह क्या है?

फ़रीदाबाद (म.मो.) पहले ज़माने में जिसे सामंतवाद कहा जाता था, जब कोई कारीगर कुछ बनाता था, तो उसे उसके नाम से जाना जाता था. जैसे ये बैलगाड़ी हरेराम बढई की बनाई हुई है. कई बार उसपर उसका नाम भी लिखा होता था. आज, पूंजीवाद में उत्पादन बहुत बढ़ गया है और हर उत्पादन अपने इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि बाज़ार में बेचने के लिए ही होता है. उत्पादन सामूहिक, सामाजिक हो गया है. आज कोई ये नहीं कह सकता कि मारुती कार किस मज़दूर ने बनाई है. क्योंकि उसके बनाने में हजारों मज़दूरों के हाथ लगे हैं. मारुती कार बनकर, शो रूम में बिकने के लिए गुडगाँव और मानेसर से निकलती है, लेकिन उसके कल पुर्जे फरीदाबाद के हज़ारों मज़दूरों के हाथों से बनते हैं. हर रोज़ उत्पादन अधिक से अधिक सामाजिक होता जा रहा है, लेकिन उसका मालिकाना व्यक्तिगत है. ये है बैर की असल वज़ह. बल्कि हर रोज़ मालिक गिनती में कम होते जा रहे हैं लेकिन उनके पूंजी के पहाड़ विशालकाय होते जा रहे हैं. मालिक चाहता है, कि सारा उत्पादन सामाजिक हो जाए, सब कुछ उसकी कंपनियां ही बनाएं, लेकिन जो भी वस्तु बने उसका मालिक सिर्फ़ वही रहे. ये पूंजीवाद में ही संभव है. मज़दूर चाहते हैं कि जैसे उत्पादन सामाजिक है, उसी तरह उत्पादन पर मालिकाना भी सामाजिक रहे, सारे समाज का रहे. इस व्यवस्था को समाजवाद कहते हैं. जैसे-जैसे उत्पादन ज्यादा से ज्यादा सामाजिक होता जा रहा है और मालिक कम होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को टिकाए रखना कठिन होता जा रहे है. मालिक और मज़दूर की इस लड़ाई का बीच-बिचाव नहीं हो सकता. निश्चित रूप से, जल्दी ही वो दिन आने वाला है, जब उत्पादन करने वाले मज़दूर एक हो जाएँगे और वे मालिक का कान पकड़कर, उसे अलग बिठा देंगे. सामाजिक उत्पादन पर सामाजिक मालिकाना क़ायम हो जाएगा. मुनाफ़ाखोर सरमाएदार भी काम करेगा तो खाएगा वर्ना भूखा मरेगा.

डीसीपी सेंट्रल एवं क्राइम मुकेश मलहोत्रा के लीगल नोटिस पर मजदूर मोर्चा का खेद

दिनांक 4-10 सितम्बर के अंक में '**पुलिस की वर्दी में डकैत**' शीर्षक से प्राकाशित समाचार को लेकर डीसीपी ने एक लीगल नोटिस मजदूर मोर्चा को भेजा है। इस बाबत हमारा कहना है कि समाचार लिखते समय ज़िले की क्राइम ब्रांच के डीसीपी मुकेश मलहोत्रा थे लेकिन पूरी घटना के दौरान वे उस पद पर नहीं थे। उनका यह कहना उचित है कि उन्होंने यह अतिरिक्त कार्यभार 27 जुलाई 2022 को ही ग्रहण किया था। इसलिये इस घटना के साथ उनका नाम अनुचित है। समाचार लिखते समय इनकी वहां तैनाती से यह भ्रम हो गया था कि सारा कांड उनकी तैनाती क दौरान ही हुआ था। नियुक्ति की तिथि का सही ज्ञान न होने के चलते ऐसा हुआ। इसका हमें खेद है। वास्तव में उइस कांड के लिये इस वहां तैनात डीसीपी नरेन्द्र कादियान उत्तरदायी हैं अर्थात् जहां डीसीपी मुकेश मल्होत्रा लिखा जाना चाहिए था। वहां डीसीपी नरेन्द्र कादियान लिखा जाना चाहिए था। नियुक्ति की तिथि की सही जानकारी न कर पाने का हमें खेद है। इसके बावजूद एक सवाल डीसीपी मल्होत्रा पर भी बनता है कि डीसीपी क्राइम का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने इस कांड को लेकर क्या किया? उनके चार्ज लेने से मात्र दो दिन पूर्व सम्पन्न हुए कांड का उन्होंने संज्ञान क्यों नहीं लिया?

उक्त समाचार में यह कहीं नहीं कहा गया कि पुलिसकर्मियों को गोवा जाने की अनुमति उन्होंने दी थी बल्कि वे बिना किसी अनुमति के ही गैर कानूनी तौर पर गोवा गये थे। इसके लिये जाने वालों तथा भेजने वालों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिये थी। इन्स्पेक्टर रवीन्दर द्वारा मौजूदा वारदात के अलावा लगातार की जा रही ऐसी ही वारदातों के लिये '**मज़दूर मोर्चा**' ने, उक्त समाचार में एसीपी, डीसीपी व सीपी से लेकर डीजीपी तक के तमाम सुपरवाईजरी अफ़सरों को दोषी माना है जिसकी वजह से पूरे पुलिस महकमे की बदनामी हो रही है। रही बात मनिंदर की फोटो की, तो जब उन्हें ही कोई एतराज नहीं है तो किसी और को क्यों होना चाहिये? दरअसल इन दोनों भाइयों की शकलें इस कदर मिलती-जुलती है कि नजरें धोखा खा जाती है। जहां तक मुकेश मलहोत्रा से उनका पक्ष जानने की बात है '**मज़दूर मोर्चा**' ने उनसे सम्पर्क करने का काफ़ी प्रयास किया था जो सफल न हो सका। कुल मिलाकर तारीखों के उलझाव में आकर डीसीपी मुकेश मलहोत्रा का नाम गलत संदर्भ में प्रकाशित होने का हमे खेद है।

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर अपनी आवाज को बुलंद रखें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या-451102010004150
IFSC Code : UBIN0545112
Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
6. सुरेन्द्र बघेल - बस अड्डा होडल - 9991742421